



नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01

अंक : 215

दि. 09.05.2026,

शनिवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

कर्मल सोफिया कुरैशी टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बड़ा राजनीतिक और कानूनी दबाव, एमपी सरकार से पूछा-आदेश के पालन में आखिर देरी क्यों?

नई दिल्ली। भारतीय सेना की अधिकारी सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा की गई विवादित टिप्पणी अब केवल राजनीतिक विवाद तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इस मामले ने न्यायपालिका, सरकार और सार्वजनिक जवाबदेही के सवाल को भी केंद्र में ला दिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार के रवैये पर गहरी नाराजगी जताते हुए साफ शब्दों में कहा कि अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अभियोजन मंजूरी पर फैसला लेने में आखिर इतनी देरी क्यों की जा रही है। अदालत की सख्त टिप्पणियों ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला वाग्वी शामिल थे, ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि अब केवल आदेश का पालन किया जाए, क्योंकि इस मामले में बहुत समय

बीत चुका है। न्यायालय का संकेत साफ था कि यह राज्य सरकार की धोमी प्रक्रिया और प्रशासनिक टालमटोल से संतुष्ट नहीं है। अदालत ने इससे पहले भी मध्य प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के भीतर अभियोजन मंजूरी पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया। पूरा मामला उस विवादित टिप्पणी से जुड़ा है जो मध्य प्रदेश के आदिवासी मामलों के मंत्री कुंवर विजय शाह ने भारतीय सेना की अधिकारी सोफिया कुरैशी को लेकर की थी। कर्मल सोफिया कुरैशी पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया ब्रीफिंग में अपनी भूमिका को लेकर चर्चा में आई थीं और सेना की ओर से जानकारी साझा करने वाली प्रमुख अधिकारियों में शामिल थीं। उनकी पेशेवर भूमिका और सैन्य सेवा को लेकर देशभर में सम्मान व्यक्त किया गया था, लेकिन इसी बीच मंत्री की टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया। बयान सामने आने के बाद विपक्ष दलों,

पूर्व सैन्य अधिकारियों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों ने इसे सेना और महिला अधिकारी दोनों के सम्मान के खिलाफ बताया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मंत्री की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण थी। उन्होंने यह दलील भी दी कि संभवतः विजय शाह का उद्देश्य कर्मल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा करना रहा होगा, लेकिन वे अपनी बात को उचित तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए। हालांकि अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह केवल "दुर्भाग्यपूर्ण" नहीं बल्कि "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" टिप्पणी थी। अदालत की इस टिप्पणी से यह संकेत भी मिला कि वह मामले को केवल राजनीतिक बयानबाजी के रूप में नहीं, बल्कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के संदर्भ में देख रही है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर



धी गंभीर टिप्पणी की कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को अपने शब्दों के प्रभाव का पूरा ज्ञान होता है। अदालत ने कहा कि राजनेता यह अच्छी तरह जानते हैं कि कब, कहाँ और किस प्रकार बोलना है। यदि यह वास्तव में जुवान फिसलने ने इस दलील को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। पीठ ने कहा कि माफ़ी केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें वास्तविक पश्चाताप दिखाई देना चाहिए। अदालत की टिप्पणियों से यह स्पष्ट था कि वह मामले को केवल एक

बयान और माफ़ी के स्तर पर खत्म करने के पक्ष में नहीं है, बल्कि पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन का आदेश दे चुका है। तीन सदस्यीय अधिकारी को भी शामिल किया गया है। अदालत ने यह कदम इसलिए उठाया था ताकि मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित की जा सके। अब अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अभियोजन मंजूरी पर जल्द निर्णय लेकर अपने पूर्व आदेश का पालन करे। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि पूरे मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। राजनीतिक स्तर पर भी यह मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे को महिला सम्मान, सेना की गरिमा और संवैधानिक जिम्मेदारी से जोड़कर सरकार पर हमलावर है। वहीं सत्तापक्ष

की ओर से नुकसान नियंत्रण की कोशिशें जारी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल एक बयान का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि अब यह इस सवाल से जुड़ गया है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग अपनी भाषा और आचरण के प्रति कितने जवाबदेह हैं। देश में सेना को हमेशा अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और सेना से जुड़े अधिकारियों के प्रति किसी भी तरह की टिप्पणी को लोग गंभीरता से लेते हैं। विशेष रूप से जब मामला महिला सैन्य अधिकारी से जुड़ा हो, तब संवेदनशीलता और भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम ने व्यापक सामाजिक प्रतिक्रिया पैदा की। कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी कहा कि राजनीतिक व्यक्तियों को सेना और उसके अधिकारियों को लेकर बयान देते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट

की टिप्पणियाँ इस बात का संकेत हैं कि अदालत सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही को लेकर सख्त रुख अपना रही है। अदालत यह स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बयान केवल व्यक्तिगत राय नहीं माने जा सकते, क्योंकि उनके शब्दों का व्यापक सामाजिक और संस्थागत प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि अदालत ने अभियोजन मंजूरी में देरी को गंभीरता से लिया और राज्य सरकार से जवाब तलब किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। तब तक राज्य सरकार को अदालत के निर्देशों के अनुरूप अभियोजन मंजूरी पर निर्णय लेना होगा। आने वाले दिनों में यह देखा महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है और एसआईटी जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्यायपालिका इस मामले को हल्के में लेने के मूढ़ में नहीं है और वह जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है।

कांग्रेस से दूरी और टीवीके को समर्थन के बाद बदले समीकरण: लोकसभा में डीएमके ने सीटिंग व्यवस्था बदलने की मांग, कनिमोड़ी का पत्र चर्चा में

नई दिल्ली। तमिलनाडु की राजनीति में चुनावी परिणामों के बाद शुरू हुई हलचल अब संसद तक पहुंच गई है। सत्ता समीकरणों में आए बदलावों और नए राजनीतिक गठबंधनों के बीच द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम) ने लोकसभा में अपने सांसदों की बैठने की व्यवस्था बदलने की औपचारिक मांग कर दी है। पार्टी की वरिष्ठ नेता और सांसद कनिमोड़ी करुणानिधि ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए डीएमके के सांसदों को कांग्रेस सांसदों से अलग सीटिंग अरेंजमेंट दिया जाए। कनिमोड़ी के इस पत्र ने संसद और राजनीतिक गतिधारा में नई चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि यह कदम केवल प्रशासनिक बदलाव का अनुरोध नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बदलते राजनीतिक गठबंधनों का औपचारिक संकेत भी माना जा रहा है। अपने पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों और गठबंधन समीकरणों में आए बदलावों के बाद डीएमके सांसदों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसदों के साथ एक ही ब्लॉक में बैठना अब उचित नहीं रह गया है। सूत्रों के अनुसार, यह पूरा घटनाक्रम तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद बदले राजनीतिक माहौल से जुड़ा है, जहां अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरकर राजनीतिक समीकरण बदल दिए।



टीवीके के सत्ता समीकरण में आने के बाद कांग्रेस ने डीएमके से दूरी बनाते हुए टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया, जिससे दोनों पुराने सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यही वह निर्णायक मोड़ था, जिसके बाद डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों में दायर सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगी। लंबे समय से दोनों दल तमिलनाडु और राष्ट्रीय राजनीति में एक साथ सहयोगी रहे थे, लेकिन हालिया घटनाक्रमों ने उनके बीच भरोसे की दूरी बढ़ा दी है। लोकसभा में सीटिंग व्यवस्था को बदलने का अनुरोध इसी बदलते राजनीतिक परिदृश्य का प्रतीक माना जा रहा है। कनिमोड़ी ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि संसद में बैठने की व्यवस्था केवल औपचारिकता नहीं होती, बल्कि यह राजनीतिक सहयोग और समन्वय का भी प्रतीक होती है। ऐसे में जब राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, तो व्यवस्था में भी बदलाव आवश्यक है ताकि पार्टी के सांसद अपनी भूमिका

अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकें। उन्होंने यह उम्मीद जताई कि लोकसभा अध्यक्ष उनके अनुरोध पर गंभीरता से विचार करेंगे और उचित निर्णय लेंगे। लोकसभा में सीटिंग अरेंजमेंट का निर्णय राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या यह कदम केवल संसदीय व्यवस्था का हिस्सा है या फिर यह कांग्रेस और डीएमके के बीच गठबंधन के औपचारिक अंत का संकेत है। पहले से ही तमिलनाडु की राजनीति में गठबंधनों में उथल-पुथल देखी जा रही है, और टीवीके के उभार ने पारंपरिक समीकरणों को काफी हद तक बदल दिया है। हालिया विधानसभा चुनावों में टीवीके के प्रदर्शन ने राज्य की राजनीति में नई ताकत का उदय दिखाया। कांग्रेस द्वारा टीवीके को समर्थन

देने के बाद डीएमके और कांग्रेस के संबंधों में दूरी और स्पष्ट हो गई। इसी पृष्ठभूमि में संसद के भीतर भी राजनीतिक दूरि दिखाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्लेषकों का मानना है कि संसद में अलग बैठने की मांग केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह भविष्य की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, लोकसभा सचिवालय ने इस पत्र को प्राप्त कर लिया है और उस पर विचार प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष को ही लेना है। यदि सीटिंग व्यवस्था में बदलाव होता है, तो यह संसद के भीतर राजनीतिक दलों के नए समीकरणों को औपचारिक रूप देगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि तमिलनाडु की राजनीति अब केवल राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति और संसद तक पहुंच चुके हैं। डीएमके, कांग्रेस और टीवीके के बीच बदलते समीकरण आने वाले समय में और भी राजनीतिक बदलावों का संकेत दे सकते हैं। फिलहाल राजनीतिक गतिधारा में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या यह दूरी स्थायी होगी या फिर परिस्थितियों के अनुसार आगे चलकर नए गठबंधन बन सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि कनिमोड़ी का यह पत्र केवल एक प्रशासनिक अनुरोध नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य का स्पष्ट संदेश है, जिसने संसद से लेकर तमिलनाडु तक राजनीतिक हलचल तेज कर दी है।

केरल कांग्रेस में नेतृत्व की जंग तेज: खरगे को सौंपी गई रिपोर्ट से बढ़ी हलचल, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कई गुट सक्रिय

कोच्चि। केरल में कांग्रेस संगठन के भीतर नेतृत्व परिवर्तन और संभावित मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रही खींचतान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। पार्टी हाईकमान द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों ने राज्य के सभी कांग्रेस विधायकों से विस्तृत बातचीत के बाद अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को सौंप दी है। यह रिपोर्ट शुक्रवार दोपहर लगभग 12 बजे प्रस्तुत की गई, जिसमें विधायकों की व्यक्तिगत और सामूहिक राय दोनों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के बाद अब पार्टी नेतृत्व पर अंतिम निर्णय लेने का दबाव और बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार, केरल कांग्रेस के भीतर सबसे मजबूत दावेदारी के.सी. वेणुगोपाल की सामने आई है। बताया जा रहा है कि लगभग 40 से 43 विधायक उनके समर्थन में हैं, जिससे वे मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार बनकर उभरे हैं। वेणुगोपाल लंबे समय से पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं। यही कारण है कि उनका नाम इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है, हालांकि अंतिम फैसला अभी भी पार्टी हाईकमान



के हाथ में है। पार्टी के भीतर चर्चा इस बात पर भी केंद्रित है कि क्या राहुल गांधी इस फैसले में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी की राय के बिना केरल जैसे महत्वपूर्ण राज्य में नेतृत्व परिवर्तन पर अंतिम मुहर लगाना मुश्किल है। वेणुगोपाल को राहुल गांधी का करीबी सहयोगी माना जाता है, इसलिए उनके समर्थन पर सहमति बनने की संभावना भी लेकर पार्टी के भीतर अलग-अलग राय सामने आ रही है। हालांकि, इस रसे में केवल एक नाम नहीं है। यदि के.सी. वेणुगोपाल के नाम पर सहमति नहीं बनती है, तो रमेश चैन्नियल को एक मजबूत विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, करीब 20 से अधिक विधायक

उनके समर्थन में हैं। चैन्नियल पहले भी राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और उन्हें एक अनुभवी और संतुलित नेता माना जाता है। पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि उनके नेतृत्व में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सकता है। इसी बीच, वी.डी. सतीशन का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। उन्हें न केवल कांग्रेस के भीतर बल्कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के सहयोगी दलों का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। इनमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस (जोसेफ गुट) और रिजोव्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी शामिल हैं। सहयोगी दलों का कहना है कि सतीशन ने विपक्ष के नेता के रूप में जमीनी स्तर पर प्रभावी भूमिका निभाई है और वे संगठन को मजबूती देने में सक्षम हैं। सूत्रों के अनुसार, पर्यवेक्षकों ने विधायकों से न केवल व्यक्तिगत राय ली, बल्कि यह भी समझने की कोशिश

की कि राज्य में पार्टी का भविष्य नेतृत्व किस दिशा में बेहतर रह सकता है। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि केरल कांग्रेस में एकरूपता की कमी और गुटबाजी लंबे समय से एक चुनौती बनी हुई है, जिसे नए नेतृत्व के जरिए संतुलित करने की जरूरत है। केरल कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर यह मंथन ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य की राजनीति में विपक्षी रणनीति को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पार्टी का उद्देश्य आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना और संगठनात्मक ढांचे को अधिक प्रभावी बनाना है। इसी वजह से मुख्यमंत्री चेहरे का चयन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय केवल किसी एक व्यक्ति के चयन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे केरल में कांग्रेस की भविष्य की दिशा भी तय होगी। यदि नेतृत्व में स्थिरता और एकता बनी रहती है, तो पार्टी अपने जनाधार को मजबूत कर सकती है, लेकिन यदि गुटबाजी बनी रहती तो इसका असर चुनावी प्रदर्शन पर पड़ सकता है।

दिल्ली से हरियाणा तक फैला आतंकी साजिश का जाल: आईएसआई समर्थित माँड्यूल के निशाने पर मंदिर, सैन्य शिविर और मीडिमाड वाले ठिकाने

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई संवेदनशील इलाकों में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रचे जाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विस इंटीलिजेंस से जुड़े एक माँड्यूल ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाने की योजना तैयार की थी। इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ, जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 'गैंग बस्ट ऑपरेशन 2.0' के तहत शाहजाद भट्टी माँड्यूल से जुड़े नौ संदिग्ध सदस्यों को विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किया। पृष्ठताछ में सामने आए खुलासों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि आरोपियों के निशाने पर धार्मिक स्थल, सैन्य प्रतिष्ठान, पुलिस थाने और मीडिमाड वाले सार्वजनिक स्थान शामिल थे। जांच एजेंसियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से पृष्ठताछ के दौरान पता चला कि माँड्यूल ने राजधानी दिल्ली के एक ऐतिहासिक मंदिर पर हमले की विस्तृत योजना तैयार की थी। आरोपियों में से एक ने मंदिर परिसर की रेकी की थी और वहां की तस्वीरें तथा अन्य जानकारी सौशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान स्थित संचालकों तक पहुंचाई थीं। जांचकर्ताओं का कहना है कि यह केवल सामान्य निगरानी नहीं थी, बल्कि हमले से पहले की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा थी। एजेंसियों को संदेह है कि माँड्यूल धार्मिक स्थल को निशाना बनाकर व्यापक दहशत फैलाना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक माँड्यूल की योजना केवल मंदिर परिसर तक सीमित नहीं थी। पृष्ठताछ में यह भी सामने आया कि हमलावर मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस



और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी निशाना बनाना चाहते थे। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि योजना गोलिबारी कर आसरातकरी और भय का माहौल पैदा करने की थी। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि आरोपियों के पास हथियारों की व्यवस्था कहाँ से होनी थी और उन्हें किस स्तर का प्रशिक्षण मिला था। दिल्ली के अलावा हरियाणा भी इस कथित साजिश का प्रमुख केंद्र था। जांच में सामने आया है कि माँड्यूल के सदस्यों ने हिसार को स्थित एक सैन्य शिविर की भी रेकी की थी। आरोपियों ने इलाके के वीडियो और अन्य सूचनाएं सीमापार बैठे अपने संचालकों को भेजी थीं। अधिकारियों का कहना है कि सैन्य प्रतिष्ठानों की निगरानी और वीडियो रिकॉर्डिंग अत्यंत गंभीर मामला है, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशील सैन्य गतिविधियों की जानकारी दुश्मन एजेंसियों तक पहुंच सकती है। इस जुलामों के बाद सैन्य और सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि माँड्यूल को हरियाणा के प्रसिद्ध मुरथल क्षेत्र में स्थित एक लोकप्रिय ढाबे को निशाना बनाने का काम सौंपा गया था। दिल्ली-सोनीपत राजमार्ग पर स्थित यह इलाका दिन-रात यात्रियों और पर्यटकों

से भरा रहता है। यहां रोजाना हजारों लोग भोजन और विश्राम के लिए रुकते हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपियों को यहां ग्रेनेड हमला करने की जिम्मेदारी दी गई थी, ताकि अधिकतम जनहानि और दहशत फैलाई जा सके। जांचकर्ताओं का मानना है कि यदि यह साजिश सफल हो जाती, तो भारी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। उत्तर प्रदेश की इस माँड्यूल की कथित योजना का हिस्सा था। पृष्ठताछ में आरोपियों ने कुछ पुलिस थानों की निगरानी किए जाने की जानकारी दी है। हालांकि सुरक्षा कार्यों से एजेंसियों ने अभी उन स्थानों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना और प्रशासनिक तंत्र में भय पैदा करना हो सकता था। यह पूरा खुलासा ऐसे समय सामने आया है जब जम्मू-कश्मीर के पहलुगाम में हुए आतंकी हमले को एक वर्ष पूरा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या गिरफ्तार माँड्यूल का किसी पुराने आतंकी नेटवर्क या सीमापार दुश्मन एजेंसियों तक पहुंच सकता है। इस जांच में डिजिटल कम्प्युनिकेशन, सौशल मीडिया गतिविधियों और वित्तीय लेन-देन को भी खंगाला जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों को अलग-अलग जिम्मेदारियों दी गई थीं। किसी को रेकी का काम सौंपा गया था, तो किसी को वीडियो और तस्वीरें भेजने की जिम्मेदारी दी गई थी। कुछ संदिग्धों

को संभावित हमले के स्थानों पर स्थानीय गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी जुटाने के निर्देश मिले थे। इससे संकेत मिलता है कि माँड्यूल संगठित तरीके से काम कर रहा था और उसकी गतिविधियां लंबे समय से चल रही थीं। सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि माँड्यूल को फंडिंग कहाँ से मिल रही थी और उसके नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे। जांच में डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन और सौशल मीडिया अकाउंट्स की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे सीमापार संचालित नेटवर्क और स्थानीय संपर्कों के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में आतंकी माँड्यूल का तरीका बदलता दिखाई दिया है। अब केवल बड़े शहरों या सरकारी इमारतों को ही नहीं, बल्कि मीडिमाड वाले सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया जा रहा है।



नवसर्जन संस्कृति हिन्दी

JioTV CHENNAL NO. 2063

Jio Air Fiber, Jio tv+, Jio Fiber, Daily Hunt, ebaba Tv, Dish Plus, DTH live OTT, Rock TV, Airtel, Amezone Fire, Roku Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गिफ्ट सिटी-गांधीनगर में 'इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट 2.0' का उद्घाटन किया

► केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की विशेष उपस्थिति
► नागरिक उड्डयन मंत्रालय, 'आईएफएससीए' और फिक्की के संयुक्त तत्वावधान में समिट का आयोजन
► देश में एयरक्राफ्ट लीजिंग इंडस्ट्रीज के लिए गिफ्टी सिटी स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण मुख्य भूमिका निभा रहा है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

► हमारा संकल्प आईएफएससीए के माध्यम से यूनीफाइड रेगुलेटरी व्यवस्था के जरिए एयरक्राफ्ट लीजिंग इंडस्ट्रीज के लिए कारोबारी सुगमता को बढ़ाना है
► गिफ्ट सिटी आईएफएससीए के साथ एयरक्राफ्ट लीजिंग इंडस्ट्रीज का सहयोग प्रधानमंत्री के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को गति देगा

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजराराम राममोहन नायडू

► गिफ्ट सिटी का एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग का सक्षम इकोसिस्टम एविएशन सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता के लिए अहम बनेगा
► भारत 2035 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनने को तैयार

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि देश में एयरक्राफ्ट लीजिंग इंडस्ट्रीज के लिए गिफ्ट सिटी स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) मुख्य भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय, आईएफएससीए और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के संयुक्त तत्वावधान में

एफएसएसआई कृत्रिम पनीर पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है, स्वास्थ्य जोखिमों के कारण कड़ा निर्णय संभव है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश की खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने बाजार में बिकने वाले कृत्रिम पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। कम पोषक तत्वों से भरपूर यह पनीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उपभोक्ता सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे बाजार से हटा दिया जाएगा। इस मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, एक उच्च स्तरीय समिति ने अक्टूबर 2025 में यह प्रस्ताव तैयार किया था और मार्च 2026 में एक बैठक में इसे आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी गई। समिति का तर्क है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा डेयरी उत्पादक होने के बावजूद, यहाँ बड़ी मात्रा में सस्ता और मिलावटी कृत्रिम पनीर बेचा जा रहा है। यह दिखने और स्वाद में असली पनीर जैसा ही होता है, जिससे उपभोक्ता प्रमित



हो जाते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कृत्रिम पनीर में प्रोटीन नगण्य और वसा अत्यधिक होती है। इसके नियमित सेवन से टाइप-2 मधुमेह और अन्य गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं। उम्मीद है कि सरकार द्वारा उठाए गए ये कड़े कदम डेयरी उद्योग में प्रारक्षिति लागू और आम आदमी के स्वास्थ्य में सुधार करेगा। देश में लगभग 1,00,00 कंपनियों के पास कृत्रिम पनीर बनाने का लाइसेंस है। नई



नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नई साझेदारियों और निवेशों के लिए विभिन्न समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही, फिक्की की नॉलेज रिपोर्ट का अनावरण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माता और हितधारक सहभागी हुए। समिति की शुरुआत में एयर इंडिया, इंडिगो, स्टाइ एयर, बैंक ऑफ इंडिया, आईएफएससीए तथा अकासा की ओर से

के फिनटेक हब के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। यह समिट गिफ्ट सिटी के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) की एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग सेक्टर की भूमिका को और व्यापक बनाकर श्रेष्ठ वैश्विक प्रथाओं को स्थानीय स्तर पर लागू करने के एविएशन फाइनेंसिंग इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने का उद्देश्य पूरा करेगी।

श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर यह भी बताया कि एयरक्राफ्ट लीजिंग इंडस्ट्रीज के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए आईएफएससीए के माध्यम से यूनीफाइड रेगुलेटरी की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पेश किए गए इस वर्ष के आम बजट में गिफ्ट सिटी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र

जबलपुर में नाव दुर्घटना ने हानी की घटना की याद दिला दी है और जल पर्यटन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी बांध में हुई दुर्घटना ने एक बार फिर जन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे वडोदरा में हुई हरनी नौका दुर्घटना की याद आ गई है। इस दुर्घटना ने नौका विहार के रोमांच और मौज-मस्ती की चार रखने वाले कई लोगों के उत्साह को निराशा में बदल दिया। दिलचस्प बात यह थी कि इस दुर्घटना के बाद भी प्रशासन के पास नौका यांग तेजी से बढ़ी है क्योंकि यह एक सस्ता विकल्प है। इसे मुख्य रूप से ताजे दूध के बनाय ताड़ के तेल, दूध पाउडर, स्टार्च और इमल्शन फाइबर के मिश्रण से बनाया जाता है। जहाँ असली ब्रांडेड चीज 450 रुपये प्रति किलो तक बिकती है, वहीं सिंथेटिक चीज 250 से 300 रुपये में उपलब्ध है। इसका व्यापक रूप से रेस्तरां और हाथों में उपयोग किया जाता है, जो ग्राहकों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए? यह बातना जरूरी है

कि तेज हवाओं और तूफान के कारण बरगी बांध पर एक क्रूज नाव फलट गई थी। दुर्घटनास्थल से नौ लोगों के शव बरामद किए गए, जबकि कई लोग लापता हो गए। इस त्रासदी के बाद यह स्पष्ट है कि यदि नाव संचालकों को प्रशिक्षण के दौरान अनिवार्य रूप से सिखाए जाने वाले सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी की जाती है, तो यह केवल लापरवाही ही होगी। इसके अलावा, जल पर्यटन के इस क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान प्रणाली की कमी भी गंभीर चिंता का विषय है।

यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि ऐसी दुर्घटनाएँ हमारे गुजरात, वडोदरा और अन्य जगहों पर भी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में हुई इस घटना को ध्यान में रखते हुए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सभी राज्य सरकारें इस दुर्घटना से सबक लें और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रबंधन प्रणालियों में व्यापक सुधार लागू करें।

(आईएफएससी) में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उद्देश्य से दिए गए टैक्स हॉलिडे और अन्व प्रोत्साहनों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आगामी दशक में भारतीय एविएशन सेक्टर में लीजिंग के लिए 50 बिलियन डॉलर के विशाल अवसर तैयार हो रहे हैं और भारत अब ग्लोबल फाइनेंस का केवल 'ग्राहक' न रहते हुए 'आर्किटेक्ट' बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। भारत वर्ष 2035 तक लगभग 2250 एयरक्राफ्ट के बेड़े के साथ, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट बनने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने केवल बड़े विमान ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए 40 से 100 सीटर विमान, हेलीकॉप्टर और सी-प्लेन की लीजिंग पर भी जोर दिया। उन्होंने इस मौके पर लक्षद्वीप में जल्द ही सी-प्लेन का संचालन शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार अब 'फ्रैक्शनल ओनरशिप' और एयरक्राफ्ट को 'इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट' के रूप में मानने में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगी। वर्तमान में, भारतीय एयरलाइंस के 80 फीसदी से

अधिक एयरक्राफ्ट आयरलैंड, सिंगापुर और दुबई जैसे विदेशी अधिकारक्षेत्रों से लीज (पट्टे) पर लिए जाते हैं। सरकार का उद्देश्य अब भारत को केवल एक मार्केट नहीं, बल्कि 'फाइनेंसिंग ज्यूरिस्ट्रिक्शन' के रूप में स्थापित करना है। आईएफएससीए के चेयरमैन श्री के. राजारमन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजनी नेतृत्व में भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के सहयोग से गिफ्ट सिटी में मेट्रो कनेक्टिविटी और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की प्रशंसा की। श्री राजारमन ने कहा कि वर्ष 2020 में जहाँ एक ही लीजिंग यूनिट नहीं थी, वहीं आज गिफ्ट सिटी में 40 से अधिक एयरक्राफ्ट लीजिंग कार्यरत हैं और 200 से अधिक विमानों तथा 84 इंजनों के लीजिंग समझौते सफलतापूर्वक हुए हैं। फिक्की सिविल एविएशन कमेटी के चेयरमैन और एयरबस इंडिया के प्रबंध निदेशक श्री जुगन वेस्टरमियर ने भी आपस विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार श्री अमित रे ने स्वागत भाषण दिया। समिट में केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय के उच्चाधिकारी, उड्डयन क्षेत्र के विशेषज्ञ, नीति निर्माता, इंडस्ट्री लीडर्स और निवेशक मौजूद रहे।

केरल में अंगदान के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा: जाली लेटरहेड, फर्जी पुलिस मंजूरी और नकली सिफारिश पत्रों का खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार

कोच्चि। मानवता और जीवन बनाने की भावना से जुड़ी अंगदान व्यवस्था को झकझोर देने वाले एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा केरल में हुआ है। राज्य पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो अंगदान करने वालों और अंग प्राप्त करने वाले मरीजों के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर अंधे तरीके से पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा था। इस मामले में मुख्यमंत्री के पुत्रियों ने पांच लोगों को हिरासत में लिया और कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने अस्पतालों, पुलिस अधिकारियों, जन्मप्रतिबंधियों और डॉक्टरों के नाम पर जाली दस्तावेजों का पूरा नेटवर्क खड़ा कर रखा था, जिसके जरिए अंगदान प्रक्रिया में जरूरी सत्यापन को प्रभावित किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए केरल पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है। कुन्नाथुण्डु पुलिस द्वारा दर्ज दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान एनक्रुलम जिले

के पेरिंगल्ला निवासी नजीब कल्लुथाय और उनकी पत्नी रशीदा, कुन्नाथुण्डु के सनी वर्गीस और उनकी पत्नी सिनी वर्गीस तथा पृथ्वीमठुम के किशोर केरि के रूप में हुई है। पुलिस को संदेह है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई लोगों को जाली दस्तावेज उपलब्ध करा चुका है। जांच एजेंसियाँ अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क का दायरा केवल केरल तक सीमित था या इसके तार दूसरे राज्यों तक भी फैले हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों को उनके घरों और पत्नीका स्थित एक डिजिटल नाम पर जाली दस्तावेजों का पूरा नेटवर्क खड़ा कर रखा था, जिसके जरिए अंगदान प्रक्रिया में जरूरी सत्यापन को प्रभावित किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए केरल पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है। कुन्नाथुण्डु पुलिस द्वारा दर्ज दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान एनक्रुलम जिले

दस्तावेज तैयार करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। इस पूरे मामले में सबसे चौकाने वाली बात यह सामने आई है कि आरोपियों ने अंगदान प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले अत्यंत संवेदनशील दस्तावेजों में हेराफेरी की थी। भारत में अंगदान की प्रक्रिया बेहद सख्त नियमों और सत्यापन के बाद पूरी की जाती है। किसी भी व्यक्ति के अंगदान या अंग प्रत्यारोपण के लिए पुलिस सत्यापन, स्थानीय निवासों की पुष्टि, डॉक्टरों की रिपोर्ट और कई बार जनप्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र तक की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी प्रक्रियाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि अंगदान पूरी तरह स्वच्छ और कानूनी हो तथा इसमें किसी प्रकार की खरीद-फरोख्त या दबाव शामिल न हो। लेकिन जांच में सामने आया है कि आरोपी इसी व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने कोच्चि के दो निजी अस्पतालों के जाली लेटरहेड तैयार किए थे।

पश्चिम रेलवे के 71वें रेल सप्ताह पुरस्कार समारोह में भावनगर मंडल को मिली तीन प्रतिष्ठित दक्षता शील्ड

पश्चिम रेलवे के 71वें रेल सप्ताह पुरस्कार समारोह का आयोजन शुक्रवार, 08 मई, 2026 को नरीमन पॉइंट स्थित यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम, मुंबई में अत्यंत गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। यह समारोह प्रतिवर्ष पश्चिम रेलवे के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उत्कृष्ट कार्यशैली, समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उनके उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित करने हेतु आयोजित किया जाता है। रेल सप्ताह समारोह के दौरान पश्चिम रेलवे के विभिन्न मंडलों एवं विभागों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर दक्षता शील्ड प्रदान की जाती है। इस वर्ष भावनगर मंडल ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए वाणिज्य, संरक्षा एवं राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निभाए के लिए तीन प्रतिष्ठित शील्ड प्राप्त कर



मंडल का गौरव बढ़ाया है। भावनगर मंडल के मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि रेल मदद शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निपटारे में नोडल एजेंसी

के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रयण पाण्डेय द्वारा मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा को उपाधि प्रदान की गई। भावनगर मंडल को प्राप्त इन उपलब्धियों से अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हर्ष एवं उत्साह का वातावरण है। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने इस सफलता का श्रेय मंडल के सभी कर्मचारियों की टीम भावना, कर्तव्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट कार्यसंस्कृति को देते हुए सभी को बधाई दी। उन्होंने भविष्य में भी इसी समर्पण एवं उत्कृष्टता के साथ कार्य करते रहने का आह्वान किया।

कुमार त्रिपाठी को प्रदान की गई। इसी प्रकार संरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य एवं बेहतर सुरक्षा मानकों के लिए 'संरक्षा शील्ड' वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी श्री सोनु कुमार को तथा राजभाषा कार्यान्वयन एवं हिंदी के प्रभावी उपयोग हेतु 'राजभाषा शील्ड' मंडल विद्युत इंजीनियर एवं राजभाषा अधिकारी श्री रामप्रति मोर्चा को प्रदान की गई। भावनगर मंडल को प्राप्त इन उपलब्धियों से अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हर्ष एवं उत्साह का वातावरण है। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने इस सफलता का श्रेय मंडल के सभी कर्मचारियों की टीम भावना, कर्तव्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट कार्यसंस्कृति को देते हुए सभी को बधाई दी। उन्होंने भविष्य में भी इसी समर्पण एवं उत्कृष्टता के साथ कार्य करते रहने का आह्वान किया।

सोना वायदा में 459 रुपये और चांदी वायदा में 3820 रुपये की वृद्धि: क्रूड ऑयल वायदा में 78 रुपये की नरमी

मुंबई: देश के अग्रणी कमांडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमांडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 189871.36 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमांडिटी वायदाओं में 28909.25 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमांडिटी ऑप्शंस में 160962.11 करोड़ रुपये का नॉनरल टर्नओवर हुआ। कमांडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3646.87 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 17673.30 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सत्र के आरंभ में 152672 रुपये के भाव पर खुलकर, 152621 रुपये के पिछले बंद के सामने 459 रुपये या 0.3 फीसदी की बढ़त के साथ 152720 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी की तेजी के संग 262360 रुपये प्रति किलो होकर यह कॉन्ट्रैट 122908 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल मई वायदा 38 रुपये या 0.25 फीसदी की तेजी के

संग 15401 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी जून वायदा सत्र के आरंभ में 152634 रुपये के भाव पर खुलकर, 153050 रुपये के दिन के उच्च और 152300 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 441 रुपये या 0.29 फीसदी की तेजी के संग 152617 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन मई वायदा रुपये के भाव पर खुलकर, 153499 रुपये के दिन के उच्च और 152571 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 152461 रुपये के पिछले बंद के सामने 439 रुपये या 0.29 फीसदी की तेजी के संग 152900 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा सत्र के आरंभ में 259999 रुपये के भाव पर खुलकर, 262880 रुपये के दिन के उच्च और 258426 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 258540 रुपये के पिछले बंद के सामने 3820 रुपये या 1.48 फीसदी की तेजी के संग 262360 रुपये प्रति किलो हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 3377 रुपये या 1.29 फीसदी की मजबूती के साथ 264594 रुपये प्रति किलो बोला



गया। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 3374 रुपये या 1.29 फीसदी की तेजी के संग 264600 रुपये प्रति किलो हुआ। मेटल वर्ग में 4707.75 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 18.25 रुपये या 1.4 फीसदी बढ़कर 1322.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मई वायदा 35 पैसे या 0.1 फीसदी बढ़कर 348.05 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 1.75 रुपये या 0.48 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैट 368.7 रुपये प्रति

किलो पर आ गया। जबकि सीसा मई वायदा 20 रुपये या 0.1 फीसदी चढ़कर 200.4 रुपये प्रति किलो हुआ। इन जिनसे के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेमिमेंट में 6263.89 करोड़ रुपये के सौदे हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 30 पैसे या 0.11 फीसदी बढ़कर

सत्र के आरंभ में 9044 रुपये के भाव पर खुलकर, 9137 रुपये के दिन के उच्च और 8866 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 78 रुपये या 0.86 फीसदी की गिरावट के साथ 8987 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा 78 रुपये या 0.86 फीसदी लुढ़ककर 8986 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा 262.6 रुपये पर खुलकर, ऊपर में 267.6 रुपये और नीचे में 261.9 रुपये पर पहुंचकर, 263.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 10 पैसे या 0.04 फीसदी बढ़कर 264 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 30 पैसे या 0.11 फीसदी बढ़कर

264.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। कृषि जिनसे में मंथा ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 988.8 रुपये के भाव पर खुलकर, 2.9 रुपये या 0.29 फीसदी की बढ़त के साथ 989.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 9101.62 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 4191.35 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 246.23 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 16.89 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 240.49 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिनसे के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 4313.55 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1924.40 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मंथा ऑयल के वायदा में 0.53 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटररेस्ट सोना के वायदाओं में 11280 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 65544 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 26799 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 369652 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 57813 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7248 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 22087 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 79546 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17110 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 34196 लोट के स्तर पर था। कमांडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मई 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 9.4 रुपये की गिरावट के साथ 382.9 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 265 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 10.95 रुपये हुआ। सोना मई 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 71.5 रुपये की गिरावट के साथ 1853 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो

407.5 रुपये की बढ़त के साथ 1671 रुपये हुआ। तांबा मई 1400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.31 रुपये की बढ़त के साथ 5.97 रुपये हुआ। जस्ता मई 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 20 पैसे के सुधार के साथ 4 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मई 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 19.6 रुपये की बढ़त के साथ 424.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू बिना बदलाव के 9.55 रुपये हुआ। सोना मई 145000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 47 रुपये की गिरावट के साथ 658.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 230000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 127 रुपये की गिरावट के साथ 1375.5 रुपये हुआ। तांबा मई 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 5.48 रुपये की गिरावट के साथ 16.18 रुपये हुआ।

► कमांडिटी वायदाओं में 28909.25 करोड़ रुपये और कमांडिटी ऑप्शंस में 160962.11 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 17673.30 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

गुजरात का 870 मेगावाट का पावर बैकअप तैयार : अतिरिक्त बिजली को संग्रहीत करता है बैटरी सिस्टम

▶▶ राज्य में मोढेरा सहित कुल पांच स्थानों पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियां कार्यान्वित, अन्य 13 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, अधिकतम मांग अवधि के दौरान करेंगे बिजली की आपूर्ति

▶▶ ग्रिड को स्थिर रखने में सहायक सिद्ध होगा, अतिरिक्त रिन्यूएबल ऊर्जा का संग्रहण कर इमरजेंसी बैकअप के रूप में भी काम करेगा

▶▶ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात अत्याधुनिक ऊर्जा सॉल्यूशंस अपनाने में अग्रणी

गांधीनगर : भारत के प्रथम सोलर विलेज मोढेरा के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से गुजरात ने देश में पहली बार सोलर पावर प्लांट के साथ एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) यानी बिजली का संग्रह करने वाली बैटरी व्यवस्था शुरू की थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज गुजरात देश भर में बैटरी स्टोरेज

प्रणाली को आगे बढ़ाने में अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। मोढेरा के बाद फिलहाल गुजरात में कुल 5 स्थानों पर 870 मेगावाट की क्षमता के साथ बैटरी स्टोरेज की व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। बैटरी स्टोरेज प्रणाली स्थापित करने के लिए अहमदाबाद, गांधीनगर, बनसकांडा, पाटण और कच्छ जिले में 13 और परियोजनाओं का रजिस्ट्रेशन किया



गया है। इन भविष्य-उन्मुख परियोजनाओं और मजबूत नीति के कारण आगामी समय में गुजरात ऊर्जा संग्रहण के क्षेत्र

में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाएगा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन अनुसार वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन

क्षमता को प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य में उल्लेखनीय योगदान देगा। हाल ही में अहमदाबाद की साणंद तहसील के चरल गांव में बैटरी ऊर्जा

स्टोरेज प्रणाली शुरू की गई है। इसके अलावा, महसाणा जिले के मोढेरा और कच्छ के लखपत में कुल 4 बैटरी स्टोरेज प्रणालियां कार्यरत हैं। राज्य सरकार ने गुजरात इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी-2025 में अत्याधुनिक ऊर्जा संग्रह करने वाली प्रणालियों को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया है। इसके आधार पर बैटरी स्टोरेज के लिए स्वतंत्र परियोजनाओं के साथ-साथ नई रिन्यूएबल ऊर्जा परियोजनाओं के साथ बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के साथ एकीकृत बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी जाती है। आगामी समय में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी मिलने के बाद व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए भी बैटरी स्टोरेज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। उसके बाद, औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ता अपने सोलर

या विंड प्रोजेक्ट के साथ बैटरी स्टोरेज की सुविधा शुरू कर सकेंगे।
क्यों जरूरी है बीईएसएस?
 बैटरी स्टोरेज सिस्टम बिजली का संग्रह करने के लिए आवश्यक है। राज्य में सोलर सहित अन्य रिन्यूएबल स्रोतों से बिजली उत्पादन दिन के दौरान बदलता रहता है। जैसे कि दिन के समय सोलर ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा होता है और शाम के समय उत्पादन नहीं होता। यदि दिन के दौरान पैदा हुई अतिरिक्त बिजली को सही तरीके से संग्रहीत किया जाए, तो शाम के समय जब मांग अधिक होती है (पीक लोड), तब उस बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। वर्तमान में, जब शाम के समय अचानक मांग बढ़ जाती है, तो बिजली आपूर्ति करने वाले ग्रिड पर लोड बढ़ जाता है। इस स्थिति में ग्रिड स्टेबल यानी स्थिर रहे, इसके लिए भी बैटरी स्टोरेज प्रणालियां आवश्यक हैं। राज्य सरकार इस दिशा में ही आगे बढ़ रही है।

गुजरात सरकार का स्मार्ट आयोजन
 गुजरात में बैटरी स्टोरेज व्यवस्था के निर्माण के लिए राज्य सरकार रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रही है। कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बीडिंग के जरिए इस क्षेत्र में आमंत्रित किया जा रहा है। बैटरी स्टोरेज सिस्टम को रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के समीप लगाने का आयोजन किया गया है, ताकि अतिरिक्त ऊर्जा को तेजी से संग्रहीत किया जा सके तथा ट्रांसमिशन लॉस और बिजली की बर्बादी को रोका जा सके। गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन (जीटीसीओ) और विद्युत वितरण कंपनियों स्मार्ट प्लानिंग के साथ ग्रिड की क्षमता के अनुसार बैटरी स्टोरेज सिस्टम के स्थल का चुनाव करती हैं। इस व्यवस्था के जरिए बैटरी स्टोरेज केवल बिजली का संग्रह ही नहीं करेगा, बल्कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को स्पीड करके ग्रिड को स्थिर भी रखेगा, साथ ही इमरजेंसी बैकअप के रूप में सहायता करेगा।

JIWO और ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच के कार्यक्रमों में सांस्कृतिक गौरव एवं देशभक्ति का सुंदर संगम

मुंबई, 8 मई। संस्कृति, साहित्य, प्रतिभा और राष्ट्र भावना से ओत-प्रोत दो भव्य कार्यक्रमों का सफल आयोजन सुप्रसिद्ध साहित्यकार, वरिष्ठ समाजसेवी एवं लोहा फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती मंजू लोहा के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ।

श्रीमती लोहा जहाँ 'जैन इंटरनेशनल वूमन ऑर्गनाइजेशन (JIWO)* के साउथ मुंबई चैप्टर की अध्यक्षा हैं, वहीं वे 'ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच' की संस्थापक-अध्यक्षा भी हैं। दोनों आयोजनों में उत्साह, रचनात्मकता, सांस्कृतिक गौरव और देशभक्ति का सुंदर संगम देखने मिला। जैन समाज की परम पूज्य विदुषी *आर्या श्री मण्णश्रीजी महाराज साहेब* की प्रेरणा एवं नेतृत्व में प्रारम्भ हुई संस्था *JIWO साउथ मुंबई चैप्टर* आज महिलाओं को संस्कृति, सेवा और सशक्तिकरण से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। लोहा चैप्टर में आयोजित *JIWO साउथ मुंबई चैप्टर टैलेट कॉम्पिटिशन* में विभिन्न प्रतिभागियों ने जैन समाज एवं भारतीय संस्कृति पर आधारित नृत्य, संगीत, अभिनय और अन्य प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में महिलाओं और समूहों ने पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सुश्री शालिनी पीरामल,



डॉ. करेन टेरि रजा तथा सुप्रसिद्ध अभिनेत्री एवं समाजसेविका सुश्री दिलजोत विशेष की अतिथियों के रूप में उपस्थित रहें और उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के पश्चात सभी JIWO सदस्यों ने गवना नृत्य का आनंद लिया, जिससे वातावरण उल्लास और उमंग से भर गया। प्रतियोगिता में विजेता बने सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की गई। इसी क्रम में लोहा कोस्टेरिया में आयोजित 'ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच' का काव्य मिलन कार्यक्रम भी अत्यंत सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इसका विषय था 'आपकी पसंदीदा जगह', जिसमें विभिन्न कवियों और साहित्य प्रेमियों ने अपनी सुंदर रचनाओं के माध्यम से भावपूर्ण

अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत कीं। इसी अवसर पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय का भी उत्सव मनाया गया। इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी गईं। उपस्थित सभी लोगों ने देश की प्रगति, विकास और मजबूत नेतृत्व के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया। दोनों आयोजन श्रीमती मंजू लोहा के सशक्त नेतृत्व, सांस्कृतिक सोच और सामाजिक समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण बने। सुश्री इंदिरा खींसरा ने कार्यक्रमों का सफल संचालन किया। श्रीमती मंजू लोहा ने सफल आयोजन के लिए दोनों संस्थाओं की सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक शक्तिशाली माध्यम बनी

▶▶ राज्य सरकार शिक्षा के सर्वांगीण विकास के जरिए 'ज्ञान शक्ति' से विकसित गुजरात की नींव मजबूत करने को प्रतिबद्ध

▶▶ आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान गोधावी में एक नया भव्य शैक्षणिक परिसर बनाएगा

▶▶ संस्थान में शिक्षा के साथ ही ध्यान, प्राणायाम और मंत्रोच्चारण जैसी योगिक पद्धतियों के माध्यम से मानव मूल्यों का संवर्धन किया जाएगा

▶▶ संस्थान का संकल्प परंपरा और आधुनिकता के संगम के साथ भविष्योन्मुखी शैक्षिक पर्यावरण प्रदान करना है

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अहमदाबाद जिले के गोधावी गांव में आकार लेने वाले नए शैक्षणिक परिसर 'श्री श्री रविशंकर विद्यामंदिर' का शास्त्रोक्त विधि से भूमिपूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक शक्तिशाली माध्यम बन गई है। जब शिक्षा में संस्कार, आध्यात्मिकता और आधुनिकता का समन्वय होता है, तभी एक जिम्मेदार नागरिक का निर्माण होता है।

मुख्यमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि आज जब साणंद क्षेत्र दुनिया के मानचित्र पर सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहा है, तब श्री श्री रविशंकर विद्यामंदिर जैसे संस्थान नई पीढ़ी को नवोन्मेषी कौशल और मूल्य-आधारित शिक्षा देकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुजित हो रहे उज्ज्वल अवसरों के लिए तैयार करे।

राज्य में शिक्षा के सर्वांगीण विकास का जिम्मा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा के लिए 63 हजार करोड़ रुपए का बड़ा बजट आवंटित करके 'ज्ञान शक्ति' से विकसित गुजरात की नींव को मजबूत कर



रही है। बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई 'नमो लक्ष्मी' और 'नमो सरस्वती विज्ञान साधना' जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के ऐसे दूरदर्शी दृष्टिकोण में यह शैक्षणिक परिसर महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस अवसर पर संस्थान के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए 'इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट' के निदर्शन की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के सोशल मीडिया के युग में योग और ज्ञान के जरिए बच्चों में चेतना जगाने का कार्य बधाई के पात्र है। मुख्यमंत्री इस मौके पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि

यह विद्या परिसर 'विकसित भारत' के निर्माण के संकल्प को साकार करने के लिए श्रेष्ठ भावी पीढ़ी का निर्माण करेगा। इस अवसर पर साणंद के विधायक श्री कनुभाई पटेल ने संस्थान को बधाई देते हुए कहा कि इस शैक्षणिक परिसर के माध्यम से देश के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का संकल्प साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ संस्थान का आध्यात्मिक प्रशिक्षण बच्चों में एकाग्रता बढ़ाने के साथ ही योग्य संस्कारों का सिंचन करके अद्भुत क्षमताएं विकसित करता है, जो उनके लिए सर्वांगीण विकास को साधने

और जीवन में आगे बढ़ने के लिए पथप्रदर्शक साबित होता है। उल्लेखनीय है कि पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के आशीर्वाद के साथ अहमदाबाद जिले के गोधावी गांव में अभी संचालित शैक्षणिक परिसर के अलावा यह नया शैक्षणिक परिसर एक सर्वसमावेशी शैक्षणिक परिसर के रूप में विकसित होगा, जिसमें सीबीएसई आधारित पाठ्यक्रम के साथ ही ध्यान, प्राणायाम और मंत्रोच्चारण जैसी योगिक क्रियाओं के द्वारा मानव मूल्यों का संवर्धन किया जाएगा।

इस परिसर में विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए स्पेर्ट्स एकेडमी, संगीत-नृत्य और नाट्य कला के लिए परफॉर्मिंग एंड क्रिएटिव आर्ट्स एकेडमी, वैसांनिक दृष्टिकोण के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एकेडमी तथा नेतृत्व के गुण विकसित करने के लिए बिजनेस एकेडमी जैसी विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस प्रकल्प के माध्यम से संस्थान का संकल्प परंपरा और आधुनिकता के संगम के साथ एक ऐसा भविष्योन्मुखी शैक्षिक पर्यावरण उपलब्ध कराना है, जहां विद्यार्थी शैक्षणिक प्रगति के साथ-साथ जीवन कौशल और मजबूत मूल्य व्यवस्था में भी पारंगत बन सकें।

71वां रेल सप्ताह: अहमदाबाद मंडल ने जीतीं 7 दक्षता शील्ड, पश्चिम रेलवे की पहली जनसंपर्क शील्ड अहमदाबाद मंडल के नाम

पश्चिम रेलवे के 71वें रेल सप्ताह पुरस्कार समारोह का आयोजन 8 मई, 2026 को मुंबई स्थित यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में किया गया। यह पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष पश्चिम रेलवे के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और उत्कृष्ट कार्य निष्पादन को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे श्री रामाश्रय पाण्डेय ने अपने संबोधन में कहा कि रेल सप्ताह के दौरान विभिन्न श्रेणियों में मंडलों एवं इकाइयों को दक्षता शील्ड प्रदान की गई, जिन्हें वर्ष 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पाया गया। पश्चिम रेलवे ने भारतीय रेलवे में ट्रेनों की समयपालनता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।



श्रेष्ठ कार्य संस्कृति को भी प्रमाणित करती हैं। इस सफलता की सबसे विशिष्ट कड़ी पश्चिम रेलवे की पहली 'जनसंपर्क शील्ड' रही, जिसे जीतकर अहमदाबाद मंडल ने जन-संवाद और सूचना प्रसार के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया है। मंडल की इस बहुमुखी सफलता में तकनीकी और परिचालन क्षेत्रों का भी विशेष योगदान रहा। विशेष रूप से कांकरिया डिपो के 'नमो भारत' जैसी आधुनिक ट्रेनों के उत्कृष्ट रखरखाव के

लिए 'मेकेनिकल बेस्ट मेंटेंड (मेल/एक्सप्रेस) ट्रांफ़ी' से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार, पालनपुर रनिंग रूम को उसके उच्च स्तरीय स्वच्छता मानकों और रेलकर्मियों के लिए उपलब्ध कराई गई उत्कृष्ट सुविधाओं हेतु 'बेस्ट मेंटेंड रनिंग रूम शील्ड' प्रदान की गई। मंडल की सामूहिक कार्यक्षमता का प्रदर्शन उन पुरस्कारों में भी दिखा जो अन्य मंडलों के साथ साझा किए गए। सिविल आधुनिक ट्रेनों के उत्कृष्ट रखरखाव के

साथ, जबकि रोलिंग स्टॉक शील्ड को मुंबई सेंट्रल मंडल के साथ साझा किया गया। परिचालन और माल ड्रुलाई के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत रखते हुए अहमदाबाद मंडल ने 'ऑपरेटिंग शील्ड' और 'बेस्ट लोडिंग एफ्ट शील्ड' को रतलाम मंडल के साथ साझा किया। इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए 'सर्वे एवं कंस्ट्रक्शन शील्ड' को उप मुख्य इंजीनियर-1 (निर्माण), अहमदाबाद द्वारा रतलाम के साथ साझा रूप से प्राप्त किया गया, जो मंडल के विस्तारवादी दृष्टिकोण और टीम वर्क की भावना को पुष्टा करता है।

इस गौरवशाली अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा ने इस सफलता का श्रेय पूरी टीम के सामूहिक प्रयासों और समर्पण को दिया। उन्होंने रेखांकित किया कि अहमदाबाद मंडल का प्राथमिक ध्येय सदैव यात्री सुरक्षा को सर्वोपरि रखना और यात्रा के अनुभव को सुखद बनाने के लिए उच्च स्तरीय मंडल को सुदृष्ट बनाना है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस सफलता के लिए बधाई देते हुए भविष्य में भी कार्य निष्पादन के इन उच्च मानकों को बनाए रखने का आह्वान किया।

रेल सप्ताह पुरस्कार में वडोदरा मंडल को मिली प्रतिष्ठित 10 दक्षता शील्ड

पश्चिम रेलवे के 71वें रेल सप्ताह पुरस्कार समारोह का आयोजन, 08 मई, 2026 को मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में किया गया। यह पुरस्कार समारोह हर साल पश्चिम रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को टीम की कड़ी मेहनत और समर्पण को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रेल सप्ताह के दौरान विभिन्न श्रेणियों में मंडलों/इकाइयों को दक्षता शील्ड प्रदान की गई। इस महत्वपूर्ण अवसर पर महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने उन मंडलों और इकाइयों को प्रतिष्ठित महाप्रबंधक की समग्र कार्यकुशलता शील्ड सहित 28 कार्यकुशलता शील्ड प्रदान कीं, जिन्हें वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सबसे कुशल पाया गया।



वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने बताया कि वर्ष 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए वडोदरा मंडल ने प्रतिष्ठित 10 दक्षता शील्ड प्राप्त कीं। मंडल को 10 शील्डों के मिलने पर मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा है कि यह अधिकारियों एवं कर्मचारियों

के सामूहिक प्रयासों का ही प्रतिफल है तथा भविष्य में भी हम इसी प्रकार से निरंतर कार्य करते रहेंगे ताकि अधिक से अधिक शील्ड वडोदरा मंडल को प्राप्त हो सके। वडोदरा मंडल ने प्रतिष्ठित अकाउंट शील्ड, कमर्शियल शील्ड, ट्रेक्शन शील्ड, मेडिकल शील्ड, स्क्रैप शील्ड, मोबिलाइजेशन शील्ड, बेस्ट वर्कशॉप ट्राफी (प्रधानमन्त्र-वर्कशॉप) प्राप्त की है। साथ ही सिविल इंजीनियरिंग शील्ड

महीने वडोदरा मंडल के पास तथा बाद के छः महीने अहमदाबाद मंडल के पास रहेगी। EnhM ट्राफी प्रथम छः महीने रतलाम मंडल के पास तथा बाद के छः महीने वडोदरा मंडल के पास रहेगी। सेप्टी शील्ड प्रथम छः महीने भावनगर मंडल के पास तथा बाद के छः महीने वडोदरा मंडल के पास रहेगी। एवं सिक्वियरीटी शील्ड प्रथम छः महीने मुंबई सेंट्रल मंडल के पास तथा बाद के छः महीने वडोदरा मंडल के पास रहेगी। इनमें सिविल इंजीनियरिंग प्रथम छः

पश्चिम रेलवे चलायेगी साबरमती और सुल्तानपुर के बीच समर स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती और सुल्तानपुर के बीच विशेष किराये पर समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण इस प्रकार है: ट्रेन संख्या 04215/04216 साबरमती-सुल्तानपुर-साबरमती स्पेशल (कुल 18 फेरे)



ट्रेन संख्या 04215 साबरमती-सुल्तानपुर स्पेशल 18 मई 2026 से 13 जुलाई 2026 तक प्रति सोमवार साबरमती से प्रातः 08:50 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 17:00 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 04216 सुल्तानपुर-साबरमती स्पेशल 17 मई 2026 से 12 जुलाई 2026 तक प्रति रविवार सुल्तानपुर से प्रातः 04:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 07:20 बजे साबरमती पहुंचेगी। इस ट्रेन में एसी-3 टियर इकॉनमी एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 04215 की बुकिंग 09 मई, 2026 से यात्री आरक्षण केन्द्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के परिचालन समय, उहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे के 71वें रेल सप्ताह समारोह में दक्षता एवं उत्कृष्टता का शानदार प्रदर्शन

▶▶ महाप्रबंधक ने विभिन्न श्रेणियों में मंडलों/इकाइयों को 28 दक्षता शील्ड प्रदान कीं

▶▶ मुंबई सेंट्रल एवं रतलाम मंडल ने संयुक्त रूप से जीती

▶▶ महाप्रबंधक की समग्र कार्यकुशलता शील्ड

▶▶ राजकोट मंडल को प्रदान की गई बेस्ट इंप्रूवमेंट शील्ड

▶▶ जनसंपर्क के क्षेत्र में नई शील्ड की शुरुआत, अहमदाबाद मंडल ने किया अपने नाम



सेंट्रल मंडल एवं अहमदाबाद मंडल ने संयुक्त रूप से प्राप्त की, जबकि सुरक्षा शील्ड मुंबई सेंट्रल एवं वडोदरा मंडल को संयुक्त रूप से प्रदान की गई। श्री विनीत ने आगे बताया कि इस वर्ष पश्चिम रेलवे द्वारा जनसंपर्क के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु एक नई शील्ड की शुरुआत की गई, जिसे अहमदाबाद मंडल ने प्राप्त किया। अहमदाबाद मंडल ने सर्वश्रेष्ठ लोडिंग एफ्ट शील्ड तथा ऑपरेटिंग शील्ड भी रतलाम मंडल के साथ संयुक्त रूप से हासिल की। इसके अलावा, अहमदाबाद मंडल के पालनपुर स्थित रनिंग रूम को सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित रनिंग रूम घोषित किया गया। वडोदरा मंडल ने अकाउंट्स, कमर्शियल, ट्रेक्शन, मेडिकल एवं स्क्रैप मोबिलाइजेशन शील्ड प्राप्त कीं। सिविल इंजीनियरिंग शील्ड

मंडल (दाहोद जिला) के प्रदान की गई। कमर्शियल स्वच्छता शील्ड राजकोट एवं रतलाम मंडलों ने संयुक्त रूप से प्राप्त की, जबकि रेल मदद शील्ड भावनगर एवं राजकोट मंडलों को संयुक्त रूप से प्रदान की गई। ट्रेक मशीन (सिविल इंजीनियरिंग) हेतु इंटर-डिविजनल शील्ड रतलाम एवं राजकोट मंडलों ने संयुक्त रूप से प्राप्त की। पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग प्रबंधन (EnhM) ट्राफी रतलाम एवं वडोदरा मंडलों को संयुक्त रूप से प्रदान की गई। राजभाषा शील्ड भावनगर मंडल को प्रदान की गई, जबकि सुरक्षा शील्ड भावनगर एवं वडोदरा मंडलों ने संयुक्त रूप से प्राप्त की। वडोदरा मंडल की प्रतापनगर वर्कशॉप को सर्वश्रेष्ठ वर्कशॉप ट्राफी प्रदान की गई, जबकि

अहमदाबाद मंडल के कांकरिया डिपो को सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित मेल/एक्सप्रेस ट्रेन ट्राफी प्रदान की गई। ये शील्ड श्री रामाश्रय पाण्डेय द्वारा संबोधित मंडल रेल प्रबंधकों, मुख्य कार्य प्रबंधकों एवं डिपो प्रभारियों को प्रदान की गई। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन (WRWVO) की अध्यक्ष श्रीमती सुजाता पाण्डेय, पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक, प्रमुख विभागाध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री पाण्डेय ने रेल सप्ताह के अवसर पर शुभकामनाएं दीं तथा महत्वपूर्ण उपलब्धियों का प्रशंसा किया। उन्होंने कर्मचारियों को उत्कृष्टता एवं उच्च कार्य मानकों की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहने के लिए भी प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त, इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी ने अतिथियों का स्वागत किया तथा उप महाप्रबंधक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।